EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

TRAI's new consultation paper on Market Structure/ Competition in cable TV services is a welcome step in the right direction. The industry has seen dramatic technology changes and other changes which needs to factored in for the future. The I&B ministry analysis that that some of the issues need further consideration by the Authority and it may provide a fresh set of recommendations in the matter looking at the subsequent developments/expansion in the M&E sector is a good development.

Department of Telecommunications (DoT) has amended the outdated Indian Telegraph Right of Way Rules (RoW) by defining a framework for laying overhead optical fibre cable (OFC), a move which can help create infrastructure necessary for the roll out of 5G technology in the country.

The amendment prescribes a one-time compensation of ₹ 1,000 per kilometre for laying overhead OFC which will lead to a uniform levy/fee charged by the local authorities. The RoW Rules until now covered only underground OFC and mobile towers.

The NTO 2.0 war between broadcasters and TRAI doesn't seem to be abating. In a new development the broadcasters and distribution platform operators (DPOs) have asserted that the New Tariff Operator (NTO) 2.0 will not just impact the service providers but will also prove detrimental for the consumers who will have to bear the brunt of price increase by the broadcasters. The TV bills of the consumers had seen an increase when the NTO 1.0 was implemented. It is expected to go up further once NTO 2.0 gets implemented.

TRAI said it is aware that prices of some of the channels announced by broadcasters are unsustainable as these are not demand driven or market determined prices and are against the interest of consumers. It remains to be seen on the further moves in this imbroglio.

Zee Entertainment Enterprises Ltd agreed to consider Invesco's demand to convene a special shareholders' meeting after the court assured that the outcome would be kept on hold for a week during which it could review the legality of the resolutions recommended by the US fund manager. More to come on this in the coming months…

(Manoj Kumar Madhavan)

केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा पर ट्राई का नया परामर्श पत्र सही दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। उद्योग ने नाटकीय तकनीकी परिवर्तन अन्य परिवर्तन देखे हैं जिन पर भविष्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। आईएंडबी मंत्रालय का विश्लेषण है कि कुछ मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा और विचार करने की आवश्यकता है और यह एमएंडई क्षेत्र में बाद के विकास/विस्तार को देखते हुए इस मामले में सिफारिशों का नया सेट प्रदान कर सकता है, यह एक अच्छा विकास है।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने ओवरहेड ऑप्टिकल फाइबर (ओएफसी) बिछाने के लिए एक रूपरेखा को परिभाषित करके पुराने भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (आरओडब्लू) में संशोधन किया है, एक ऐसा कदम जो देश में 5जी तकनीकी के रोलआउट के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने में मदद कर सकता है।

*संशोधन में ओवरहेड ओएफसी बिछाने के लिए **1000** रूपये प्रति किलोमीटर का एकमुश्त मुआवजा निर्धारित किया गया है जिससे स्थानीय अधिकारियों द्वारा एक समान शुल्क/शुल्क लगाया जायेगाा। आरओडब्लू नियम अब तक केवल भूमिगत ओएफसी और मोबाइल टावरों को ही कवर करते थे।*

*प्रसारकों और ट्राई के बीच एनटीओ **2.0** की जंग थमती नहीं दिख रही है। एक नयी स्थिति विकास में प्रसारकों और वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) ने जोर देकर कहा है कि नया टैरिफ आदेश (एनटीओ) **2.0** न केवल सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करेगा, बल्कि उन उपभोक्ताओं के लिए भी हानिकारक साबित होगा, जिन्हें प्रसारकों द्वारा मूल्य वृद्धि का खामियाजा भुगताना पड़ेगा। एनटीओ **1.0** लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के टीवी बिलों वृद्धि देखी गयी थी। एनटीओ **2.0** के लागू होने के बाद इसके और बढ़ने की उम्मीद है।*

ट्राई ने कहा कि वह जानता है कि प्रसारकों द्वारा घोषित कुछ चैनलों की कीमतें टिकाऊ नहीं है, क्योंकि ये मांग आधारित या बाजार निर्धारित मूल्य नहीं है और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है। यह इस गतिरोध में आगे के चालों को देखा जाना बाकी है।

जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक विशेष शेयरधारकों की बैठक बुलाने की इन्वेस्को की मांग पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की, जब अदालत ने आश्वासन दिया कि परिणाम को एक सप्ताह के लिए रोक दिया जायेगा, जिसके दौरान वह अमेरिकी फंड मैनेजर द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों की वैधता की समीक्षा कर सकता है। आने वाले महीने में हमें बहुत कुछ देखने-सुनने को मिलेगा…

(Manoj Kumar Madhavan)